(प्रशासन) जे.पी. जोशी के अनुसार सम्मेलन में देश भर से सहकारी बैंकों व संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आमन्त्रित किया गया है। इसमें विभिन्न तकनीकी विषयों पर आयोजित सत्रों में विषय विशेषज्ञों द्वारा व्यापक चर्चा की जाएगी। सम्मेलन में उदयपुर, जयपुर, सिरोही एवं जालौर सहित राजस्थान से कई प्रतिभागी भाग ले रहे हैं।

आशापूर्णा वैली में आवास लेने में जनता का भारी उत्साह

जोधपुर/नि.सं.। आशापूर्णा बिल्डिकॉन लिमिटेड जोधपुर की जनता को राजस्थान न्यू हाईकोर्ट के पास पूर्ण विकसित टाउनशिप आशापूर्णा वैली में मात्र 15.50 लाख रुपए में आवास पाने का मौका दे रही है। लोगों में इसको लेकर का भारी उत्साह देखने को मिला है। लोग कंपनी के मुख्य कार्यालय एवं वैली साइट विजिट पर प्रोजेक्ट की बहुत सराहना कर रहे हैं व अपने जरूरत के अनुसार मकान एवं प्लॉट बुक कराये। आशापूर्णा ग्रुप के डीजीएम सेल्स एण्ड मार्केटिंग अरविन्द सिंह भाटी ने बताया कि इस परियोजना ने जोधपुर प्रॉपर्टी मार्केट में काफी हलचल मचायी है। परियोजना में 45 गुणा 70, 45 गुणा 60, 40 गुणा 60, 30 गुणा 60 एवं 25 गुणा 50, के भूखंड उपलब्ध हैं। वैली में करीब 250 परिवार रह रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में जी प्लस 2 में स्वतंत्र फ्लोर फ्लेट भी बनकर तैयार है। आशापूर्णा वैली टाउनशिप सभी सुविधाओं से परिपूर्ण है।

कोयला आधारित बिजलीघरों को बंद करने की घोषणा का विरोध

कोटा/नि.स.। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में देश भर में चल रहे कोयला आधारित बिजलीघरों को बंद करने की घोषणा कर बेरोजगारी के दंश को ओर बढ़ा दिया है। सरकार के इस कदम से लाखों लोगों की आजीविका पर संकट के बादल छाए रहेंगे। राजस्थान विद्युत उत्पादन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रामसिंह शेखावत ने कहा कि राज्य में सबसे पुराने बिजलीघर कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना 1983 में हुई थी। वर्तमान में इसकी 7 इकाइयों से 1240 मेगावाट क्षमता से अपेक्षाकृत सस्ती बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। लेकिन केंद्र सरकार कार्बन उत्सर्जन के नाम पर सरकारी क्षेत्र के चालू बिजलीघरों को बंद करने की योजना बनाकर जनता पर कुठाराघात करना चाहती है। सौर व पवन ऊर्जा संयंत्र वैकल्पिक स्त्रोत है, जिनकी क्षमता मांग की तुलना में बहुत कम है। यदि राज्य में थर्मल बिजलीघरों को धीरे-धीरे बन्द किया गया तो रोजगार छीनने के साथ ही आम जनता पर महंगी बिजली की मार भी पड़ेगी।

पहले हुआ था आंदोलन : शेखावत ने कहा कि राज्य में वसुंधरा सरकार के कार्यकाल में थर्मल अभियंताओं, कर्मचारियों व श्रमिकों ने कालीसिंध, छबड़ा व कोटा थर्मल में निजी विनिवेश करने तथा उनको बेचने का कड़ा विरोध किया था, जिसके दबाव में राज्य सरकार ने निर्णय वापस लिया था उन्होंने बताया कि कोटा सुपर थर्मल में कई वर्षों से तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती बन्द है। 1983 में भर्ती अभियंताओं व कर्मचारियों की निरंतर सेवानिवृति होने से थर्मल में मेन पावर घटकर 50 फीसदी रह गई है। इसके बावजूद थर्मल से पूरी क्षमता से बिजली उत्पादन किया जा रहा है। इस समय लगभग 2500 ठेका श्रमिकों को कोटा थर्मल में रोजगार मिला हुआ है। यदि बिजलीघर की चार पुरानी इकाइयों को बंद किया गया तो एक हजार से अधिक अभियंता, कर्मचारी व श्रमिक समय से पूर्व बेरोजगारी की चपेट में आ जाएंगे। सरकार नए उद्योग स्थापित करने की बजाए चालू उद्योगों को बंद करने की योजना बनाकर दिया तले अँधेरा जैसा आत्मघाती कदम उठा रही है। कर्मचारी व श्रमिक संगठनों द्वारा इस निर्णय का कड़ा विरोध किया जाएगा।

बीएफएल एसेट फिनवेस्ट लिमिटेड
(पूर्व में बीएफएल डवलपर्स के रूप में जानते थे)
पंजीकृत कार्यालय : 1, तारानगर, अजमेर रोड, जयपुर-302006, फोन : 9214018877
E. : bfldevelopers@gmail.com, W.: www.bflfin.com • CIN: L45201RJ1995PLC010646

सूचना

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता एवं डिस्क्लोजर आवश्यकता) रेग्यूलेशन 2015 के नियम 47 के तहत यह सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक 12 फरवरी, 2020 बुधवार को सायं 4.00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 1, तारानगर, अजमेर रोड, जयपुर-302006 में आयोजित की जा रही है, जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 दिसम्बर 2019 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही के लिए कंपनी के गैर अंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं स्वीकृति दी जायेगी और लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लाया जायेगा। यह सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.bflfin.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

वास्ते बीएफएल एसेट फिनवेस्ट लिमिटेड
(पूर्व में बीएफएल डवलपर्स लिमिटेड के रूप में जानते थे)
सीएस सुरभि रावत
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी (M.No. A49694)

दिनांक : 3 फरवरी, 2020
स्थान : जयपुर

कारण सहारा की स्थापित परम्परा के विपरीत विलम्ब हो रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायाल फलस्वरूप हम अपनी परिसंपत्तियों को बेचकर, से धन जुटाते हैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सहारा-सेबी खाते में जमा हो जायेंगे, उसमें से कार्य हेतु उपयोग नहीं कर सकते, यहाँ तक भुगतान हेतु भी नहीं।

जबकि सहारा की परिसंपत्तियाँ उसकी कुल दे गुना ज़्यादा हैं।

तीन गुना परिसंपत्तियों के बावजूद परेश

अब बात यह आती है कि सहारा के पास जब इत बेच कर संकट से बाहर क्यों नहीं आता। इस स सब कुछ हमारी पहुँच के भीतर है लेकिन मा प्रतिबंध की अड़चन के कारण पहुँच से बाहर भी निर्माण का व्यवसाय करने की थोड़ी सी छूट मि ठीक हो गया होता।

दरअसल, पूरे हिंदुस्तान में हमारी हज़ारों एकड़ में बिखरी पड़ी है लेकिन ये सारे भूखंड बड़े क्षेत्रफ एकड़ के हैं। अकेली ऐम्बी वैली का क्षेत्रफल 900 यह है कि बड़े भूखंडों के खरीदार हिंदुस्तान (Real Estate) में मंदी है। ऐसी सूरत में जो ए वे एक भूखंड को उसके वास्तविक मूल्य के चौथ लेना चाहते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश मूल्य का सौदा करना हमारे लिए संभव नहीं है क के 90 प्रतिशत के नीचे बेचने की इजाज़त नहीं है

बड़े भूखंड पर यदि टाउनशिप (कॉलोनी) विकसि परिस्थितियाँ आयेंगी। पहले कि भूखंड का आंत जैसे-सड़क या अन्य सुविधाएं निर्मित करने हेतु प आवास डेवलपमेंट करने हेतु आवंटियों से बतौर हैं तो इससे जो पैसा आयेगा वह इस अजीब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सहारा-सेबी एकाउं हाउसिंग डेवलपमेंट के व्यवसाय की गाड़ी आगे हैं लेकिन उनका विकास कर व्यवसाय नहीं किय चल रहे थे आज वो भी रुक गये हैं, क्योंकि धन क

ख़ुशी की बात :

यह ख़ुशी की बात है कि दो सम्मानित विदेशी रकम लेकर हमारे साथ रियल एस्टेट एवं सिटी रही हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को करारों पर दस्तखत हो चुके हैं जिससे इसी व परेशानियाँ सुलझेंगी।